IJAER/January-February-2025/Volume-14/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

"चौ० चरण सिंह : एक संघर्षशील किसान नेता के रूप में"

डॉ० राजकुमार सिंह[1]
असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास विभाग
शहीद मंगल पाण्डे राजकीय महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ

प्रमोद[2]
शोध छात्र (इतिहास विभाग)
शहीद मंगल पाण्डे राजकीय महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ
E-mail: parmodkmr24@gmail.com

सारांश

चौ० चरण सिंह ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसानों की समस्याओं को ठीक प्रकार से समझा भी और किसानों के हित में अपनी आवाज भी बुलन्द की एवं विधान सभा (धारा सभा) तथा लोकसभा की कार्यवाहियों में भी उन्होंने किसान हित में बढ़–चढ़कर भाग लिया तथा किसानों के हित में कभी भी आन्दोलनात्मक मार्ग का अनुसरण नहीं किया। यहां यह बात बहुत रोचक है कि चौ० चरण सिंह ने अपने आपको सदैव गाँधी का अनुयायी सिद्ध करने अथवा गाँधीवाद से जोड़ने का भरसक प्रयत्न किया तथा गाँधी जी की अर्थनीति के आधार पर ही अपनी आर्थिक नीति विकसित की। वहीं वह सदैव नेहरु को अपना नेता मानने के बावजूद, नेहरु के स्थान पर सरदार पटेल के नजदीक प्रतीत होते हैं। उनके अनुयायियों ने उन्हें सदैव सरदार पटेल के समतुल्य लौह पुरुष तथा किसान हितैषी सिद्ध करने का प्रयत्न किया। वे गाँधी के उन सिद्धान्तों में विश्वास नहीं रखते थे, उनका तर्क था कि ये तरीके एक लोकतांत्रिक देश के लिए अनुचित हैं। जहां वोट के द्वारा अलोकप्रिय सरकार को बदला जा सकता है। अतः अपनी ही सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन, घेराव, सत्याग्रह, हड़ताल तथा आमरण अनशन जैसे विरोध अथवा संघर्ष के साधनों को संविधानेत्तेर यहां तक कि किसानों के किसी संगठन या यूनियन बनाने के भी वह पक्षधर नहीं थे। उनके अनुसार किसानों को अपने हितों के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा अपने वोट की कीमत को समझना चाहिए। अतः जरूरत आन्दोलन की नहीं वरन् जागरूकता की है और यही कार्य चौ० चरण सिंह ने किया।

मुख्य शब्दः खेतीहर, सीरदारी, भूमिधर, गुटिय राजनीति, वर्गीय चेतना।

प्रस्तावनाः–

शोधार्थी अपने शोध–पत्र में जिस व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहा है उस महान आत्मा का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। "इतिहासकार एवं लोग समान रूप से उन्हें किसानों के चैम्पियन के रूप में संदर्भित करते हैं।" चौ० चरण सिंह जी का जन्म एक हिन्दू (जाट) परिवार में 23 दिसम्बर,

1902 ई० को ग्राम नूरपुर मेरठ, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत (वर्तमान में हापुड़ जिला, उ०प्र०) में एक काली मिट्टी के टेढ़े–मेढ़े अनगढ़ फूस की छत वाली मढ़ैया में, चंद्रवंश में शिवि गौत्र में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चौ० मीर सिंह एवं माताजी का नाम श्रीमती नैत्र कौर था। ग्रामीण समाज, कृषकों एवं गरीबी की समस्याओं को अपनी बाल्यावस्था व युवावस्था में देखा। उनका पूरा राजनीतिक जीवन गाँव और किसान की समस्याओं और उनके समाधान ढूंढने के चिन्तन पर ही केन्द्रित रहा। स्वतंत्र भारत में वे किसानों के सबसे बड़े प्रवक्ता थे।

आजादी के बाद किसान, जो आजाद भारत की असली ताकत थे, उनकी कोई आवाज नहीं थी। इसका कारण था उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव था। चौ० चरण सिंह ने उनमें राजनीतिक चेतना जागृत की तथा उनके मन में सत्ता में भागीदारी की भावना पैदा की। उन्होंने किसानों में वर्गीय चेतना जागृत करके उन्हें स्वतंत्र वर्ग के रूप में संगठित होने की प्रेरणा दी। यह एक ऐसा कार्य था जिसे समाजवाद एवं वामपंथ का दंभ भरने वाले बहुत से नेता भी न कर पाये।

देश की राजनीति को जन–साधारण की राजनीति बनाने का श्रेय चौ० चरण सिंह को ही जाता है। यह सब चौधरी साहब का ही करिश्मा है। उनके केन्द्र में आने से पहले बनी योजनाओं में जाहिर तौर पर किसानों के लिए छः फीसद रकम खर्च करने की बात कह पाना किसी भी सदस्य के बस की बात नहीं थी। खेती, गाँव और देहात के लिए साठ फीसदी बजट की रकम खर्च करने की बात जरूर कही जाती है।

चौ० चरण सिंह कहा करते थे कि किसानों की एक आँख खेत की मेड़ पर और एक आँख लखनऊ एवं दिल्ली पर होनी चाहिए। अर्थात् इस बात पर कि सरकार क्या कर रही है, तभी देश सही दिशा में आगे बढ़ सकता है, यदि किसान खुशहाल हो जायेगा तो देश खुशहाल हो जायेगा।

चौ० चरण सिंह की इच्छा थी कि जिस तरह से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार किसी एक दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्हें इस बात का दुःख था कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे देश में किसान दिवस नहीं मनया जाता, लेकिन वे किसान दिवस को अवकाश दिवस (राष्ट्रीय छुट्टी) के रूप में नहीं वरन् संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहते थे, जबकि किसान को न्याय दिलाने के लिए उसके अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष किया जाए और उस संघर्ष के लिए किसान दिवस के दिन संकल्प लिया जाए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनवरी, 1959 के नागपुर अधिवेशन में पं० जवाहर लाल नेहरु ने जब सहकारी खेती का प्रस्ताव पेश किया तो चौ० चरण सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य की चिन्ता न करते हुए उसका कड़ा विरोध किया और प्रस्ताव के विरोध में जोरदार भाषण दिया, यद्यपि इसकी कीमत उन्हें अपने (राजस्व मंत्री) पद से इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी और डेढ़ वर्ष तक के लिए उन्हें मंत्रिमण्डल से बाहर रहना पड़ा। यद्यपि 1959 में जब वे नेहरु के साथ उलझ पड़े थे, जब सोवियत संघ और सहकारी खेती के अंत का पूर्वानुमान कोई नहीं कर पाया था। तथापि वक्त ने चौ० चरण सिंह को सही साबित कर दिया।

चौ० चरण सिंह ने सरकारी सेवाओं में किसी जाति विशेष के लिए आरक्षण की मांग न करके सम्पूर्ण कृषक संतानों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग रखी। 1939 में उत्तर प्रदेश की धारा सभा (विधानसभा) में एक प्रस्ताव रखा जिसमें 50 प्रतिशत उच्च प्रशासनिक पद खेतिहर के लिए आरक्षित करने की बात कही गयी थी, परन्तु तत्कालीन सरकार ने कोई विचार नहीं किया। बाद में 1947 में उन्होंने पुनः इस विषय की महत्ता को सिद्ध करते हुए एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था– "किसान संतान को 50 प्रतिशत आरक्षण क्यों?" उन्होंने 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बताया कि 75.5 प्रतिशत आबादी खेतिहर लोगों की है। इसलिए यर्थाथ में संयुक्त प्रान्त में खेती में लगे वर्ग को जनता कहा जा सकता है। सरकार के समस्त विभागों का निर्माण इसी जनता के हितों को पूरा करने के लिए किया गया है। सरकारी सेवा के आंकड़े उनके अभिभावक या पिताओं के पेशे के आधार पर उपलब्ध नहीं है, किन्तु यह बात बिना किसी विरोधाभास के कही जा सकती है कि उनके अनुपात, सैनिक सेवाओं के अतिरिक्त, किसी भी हालत में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

हमारे देश में वे जातियां जिनके वंशज सरकारी सेवाओं में अधिकार जमाये हुए हैं, प्रायः वे हैं, जिनको अंग्रेजों द्वारा अप्रत्याशित महत्व और ख्याति प्रदान की गयी थी। इनमें साहूकार, बड़े–बड़े जमींदार, ताल्लुकेदार, आढ़ती, व्यापारी अथवा वे लोग हैं जो प्रायः इन लोगों द्वारा शामिल किए गए हैं, जिनमें वकील, डॉक्टर और ठेकेदार आते हैं। इन जातियों ने अंग्रेजों की आधीनता में पिछले 200 वर्षों में जनता का हर प्रकार से शोषण किया था। इन वर्गों के हित और विचार पूर्णतः स्पष्ट रूप से जन समाज के विरोधी हैं। यह किसी औद्योगिक व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की गई दिशा, रूझान तथा विचार से अलग होती है। काउण्ट रिचर्ड औडनओ कलर्जी ने अपनी पुस्तक 'टोटेलिटेरियन स्टेट अगेंस्ट मैन' में किसान के विषय में लिखा है– 'वह प्रकृति के बीच में, प्रकृति के साथ, पशु और पेड़–पौधों का सहजीवी बनकर रहता है। इस कारण दुनिया के विषय में उसका अन्दाज उस शहरी आदमी से बहुत भिन्न होता

है। संसार तथा वस्तुओं के प्रति उसका रूख सहज होता है, मशीनवत नहीं। सम्पूर्णानन्द के इस विचार से चौ० चरण सिंह ने प्रेरणा पायी– "न्यायाधीश तथा विधि–निर्माताओं को इरादतन अनुचित होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य होने के नाते वर्ग हितों एवं जातीय सम्बन्धों द्वारा उन पर लगायी गयी सीमाओं से ऊपर उठ सकना उनके लिए असम्भव होगा।"

इसके लिए उन्होंने एक दूसरा प्रमाण लन्दन का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत किया। लंदन में बढ़ती हुयी आबादी का अध्ययन करते हुए सर हरबर्ट लैवल्यू स्मिथ ने एक आधी शती से पहले कहा था कि, 'देहात से शहर में आने वाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से विशाल होता है और उसकी नितान्त कीमती मानसिक योग्यताओं का अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि विशेष प्रतिष्ठा तथा विशेष दायित्वपूर्ण नौकरियों के लिए लंदन में देहाती क्षेत्र से आया व्यक्ति अधिक पसंद किया जाता है।'

किसानों के हित में संघर्ष का एक उदाहरण 1962 में कृषि मंत्री के रूप में उनके द्वारा भूमिकर में वृद्धि का विरोध करने से मिलता है। दरअसल, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून में यह व्यवस्था थी कि सीरदारी और भूमिधरों द्वारा चुकाए जा रहे भूमिकर अगले 40 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेंगे। फिर भी दस साल बाद ही 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्द्रभानु गुप्त ने उसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि करने की बात छेड़ दी। चरण सिंह ने उस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया और मुख्यमंत्री के समक्ष अपने 29 सितम्बर, 1962 के विस्तृत गोपनीय नोट के जरिए विरोध का बैद्धिक पक्ष पेश किया, तो नीचे दिया जा रहा है–

"तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए धन जुटाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जोत–भूमि–कर विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य जोतदारों द्वारा आज चुकाए जा रहे भू–राजस्व में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना है। राज्य सरकार को यह कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए, इसके निम्नलिखित पांच बहुत ही ठोस कारण हैं–

(अ) किसानों की आर्थिक स्थिति उनके वित्तीय बोझ को बढ़ाने की अनुमति नहीं देती।

(आ) उत्तर प्रदेश में भूमि पर पहले से ही करों का भारी बोझ है तथा ग्रामीण या कृषक कर चुकाने के प्रयास में पीछे नहीं रहे हैं।

(इ) कर आवश्यक नहीं है, क्योंकि अन्य तरीकों से धन जुटाया जा सकता है और वांछित फल प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ई) राजनीतिक दृष्टि से यह विधेयक कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसान देह कदम सिद्ध होगा।

(उ) भू–राजस्व में कोई वृद्धि जनता को विधिवत् दिये गये उस आश्वासन और जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून, 1952 में समाविष्ट इस प्रावधान के विरूद्ध होगी कि अगले 40 साल तक राज्य के राजस्व में वृद्धि नहीं होगी।"

मामला योजना आयोग और नई दिल्ली के कांग्रेसी नेतृत्व तक जा पहुंचा, अन्ततः प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। इस प्रकार चौ० चरण सिंह के कठोर रूख ने किसानों को भूमिकर में वृद्धि से राहत दिलवायी।

1977 में जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो चौ० चरण सिंह उस सरकार में गृहमंत्री बने। चौ० चरण सिंह किसानों के मुद्दों पर ही उलझे रहे। जनता पार्टी एवं सरकार की नीति निर्धारित कराने, पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने तथा बजट बनाते समय, हर जगह उन्होंने किसानों और ग्रामीण विकास के मुद्दों को उठाया। इससे जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से उनके विवाद भी हुए। वे मंत्रिमण्डल में अकेले पड़ गये लेकिन फिर भी उनकी आवाज दबी नहीं बल्कि और मुखर हो उठी। जब उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से पृथक कर दिया गया तो अपने 77वें जन्मदिन पर 23 दिसम्बर, 1978 को उन्होंने दिल्ली में वोट क्लब पर विशाल किसान रैली की, जिसने उनमें नई शक्ति का संचार किया और वित्त मंत्री के रूप में उनकी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में पुनः वापसी हुई।

दिल्ली में हुई विशाल किसान रैली में श्री रविराय ने 'गाँधीवादी अर्थनीति' का एक 'किसान घोषणा पत्र' प्रस्तावित किया था, जिसका समर्थन श्री एस०एन० मिश्र ने किया था। उस किसान मैनीफेस्टो के कुछ विचार इस प्रकार थे–

"देहाती क्षेत्र के शोषण की प्रवृत्ति अधिक बढ़ती जा रही है और इस क्षेत्र में थोड़े से लोगों की वैयक्तिक सम्पत्ति तथा सामाजिक विकास इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकता कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के आर्थिक स्तर को जबर्दस्त आघात पहुंचा है। इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा द्वारिका से लेकर कामख्या तक के समस्त भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह द्वारा नयी सामाजिक संरचना सम्बन्धी अत्यंत प्रेरणादायक दर्शन का स्वागत करते हैं और हम इस बात के लिए कमर कस कर तैयार हैं कि देश के समस्त ग्रामीणों को संगठित करके देहात में फैली व्यापक गरीबी पर इस प्रकार कसकर प्रहार किया जाए कि हमारा आन्दोलन मानव–इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय बन जाए।"

'किसान घोषणा पत्र' के इन बीस सूत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए चौ० चरण सिंह के पास एक विशिष्ट सोच व कार्यक्रम था, जिसको लागू कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया।

उ०प्र० की राजनीति मे गुटीय राजनीति का एक विशेष महत्व रहा है। उत्तर प्रदेश को भारत का एक छोटा रूप कहा जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौ० चरण सिंह के अतिरिक्त मोहन लाल गौतम एक प्रमुख नेता थे जो कि कांग्रेस के प्रारम्भिक काल में गुटीय राजनीति में एक गुट का प्रतिनिधित्व करते थे। गोविन्द वल्लभ पंत के केन्द्र में चले जाने के बाद तथा सम्पूर्णानन्द के प्रभावहीन हो जाने के बाद जहां एक ओर उ०प्र० की गुटीय राजनीति में चन्द्रभानु गुप्त एक गुट के नेता के रूप में उभर कर सामने आये वहीं उनके विरूद्ध मोहनलाल गौतम एक गुटीय राजनीतिक नेता के रूप में उभरकर सामने आये। मोहनलाल गौतम की प्रभावहीनता की स्थिति में उ०प्र० में सी०बी० गुप्ता गुट के विरूद्ध कमला पति त्रिपाठी एक गुटीय नेता के रूप में उभरकर सामने आये। इन दोनों गुटों से अलग एक तीसरे गुटीय नेता के रूप में चौ० चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक पहचान बना रखी थी। कमलापति त्रिपाठी ब्राह्मण जाति से थे, केन्द्रीय राजनीति में नेहरु के समर्थक थे और समूचे उ०प्र० में ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किए जाते थे। चन्द्रभानु गुप्त ने लाईसेंसों के माध्यम से उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का सहारा लेकर एक गुटीय नेता के रूप में अपनी स्थिति बहुत अधिक मजबूत कर रखी थी। यहां एक तीसरे गुट के नेता के रूप में चौ० चरण सिंह के सामने अपनी स्थिति को सशक्त बनाये रखने का इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं था कि वो कृषिरत् पिछड़ी जातियों को संगठित कर उनके नेता के रूप में अपने आपको स्थापित कर सकते थे।

कांग्रेस से अलग होकर जन कांग्रेस के नेता के रूप में चौ० चरण सिंह संयुक्त विधायक दल के नेता के रूप में उ०प्र० के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। फिर जन कांग्रेस को भारतीय क्रांति दल में मिला दिया तथा भारतीय क्रांति दल के एकछत्र नेता के रूप में उभरे।

चरण सिंह ने जब भारतीय क्रांति दल के नेता के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया तथा कृषिरत् 'अजगर' जातियों को संगठित करने के प्रयास किए तभी उनके अनुयायियों ने उन्हें एकमात्र कृषक नेता के रूप में सराहा। वस्तुतः कांग्रेस छोड़कर ही उन्हें कांग्रेसी मंत्री के रूप में उनके द्वारा किये गये कृषक हित के कार्यों के कारण पारितोषिक स्वरूप कृषक नेता की छवि बनाने का मौका मिला।

निष्कर्षः–

चौ० साहब अपनी मान्यताओं में पूर्वाग्रह की सीमा तक दृढ़ थे। ग्रामीण भारत को ही असली भारत मानते हुए उन्होंने गाँवों और शहरों के बीच की असमानता को कम करने की बराबर आवाज उठायी थी। वे वास्तविक रूप में किसानों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध होने की काबलियत रखते थे। उन्होंने कुटीर उद्योगों की वकालत की। कृषि सुधार पर निरन्तर बल दिया किन्तु सवर्णों का वरिष्ठता और सत्ता पर उनका एकाधिकार चौ० साहब के मन में निरंतर कड़वाहट पैदा करता रहा। इसीलिए एक तरफ उनकी हैसियत को हमेशा बड़े किसानों के नेता के रूप में सीमित किया जाता रहा है और दूसरी तरफ यह प्रचार भी होता रहा है कि वह हरिजनों के हितरक्षक नहीं है, लेकिन ये मात्र भ्रम है न कि वास्तविकता। आजाद भारत में चौ० साहब ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और न केवल गरीब और अमीर के बीच, बल्कि शहर और गाँव के बीच की असमानता खत्म करने की बात कही और स्वयं को एक किसान नेता के रूप में स्थापित किया।

संदर्भ सूची

1. इन्द्र कुमार गुजराल, एक सादगी पसंद प्रधानमंत्री चौ० चरण सिंह स्मृति और मूल्यांकन, किसान ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1965, पृ० 75–76 (संकलनल ज्ञानेन्द्र रावत)
2. साक्षात्कार–मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उ०प्र०
3. मधु दण्डवते–असली भारत, दिसम्बर, 1990, पृ० 11
4. उपर्युक्त, पृ० 11
5. चौ० चरण सिंह, आर्थिक विकास के सवाल और बौद्धिक दिवालियापन, किसान ट्रस्ट, नई दिल्ली, मई, 1986, पृ० 13
6. कुंवर नटवर सिंह, असली भारत, दिसम्बर, 1999
7. चरण सिंह, उ०प्र० में भूमि सुधार और कुलक वर्ग, किसान ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1986, पृ० 207
8. उपर्युक्त, पृ० 208
9. उपर्युक्त, पृ० 209
10. उपर्युक्त, पृ० 210
11. उपर्युक्त, पृ० 214
12. उपर्युक्त, पृ० 214
13. उपर्युक्त, पृ० 151
14. उपर्युक्त, पृ० 193
15. उपर्युक्त, पृ० 194
16. उपर्युक्त, पृ० 199
17. आर०के० हुड्डा, मैन ऑफ मासेज, नई दिल्ली, 1986, पृ० 35

18. उपर्युक्त, पृ० 36

19. पी०सी० वशिष्ठ–भारतीय क्रांति दल एवं उसके नेता, शोध ग्रंथ, मेरठ विश्वविद्यालय, 1980, पृ० 28–29, 93–97

20. उपर्युक्त, पृ० 28–29, 96–97

21. उपर्युक्त, पृ० 28–29, 96–97

22. दिनमान, 23–29 दिसम्बर, 1979, पृ० 15

23. उपर्युक्त, पृ० 15–16

24. सतपाल मलिक– चौ० चरण सिंह के विचार, ग्राम शक्ति केन्द्र, दिल्ली, पृ० 15